कृषि ऋण माफी से मुद्रास्फीति 0.2 प्रतिशत बढ़ेगी: रिजर्व बैंक

मुंबई 12सितंबर(ए)। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि कृषि ऋण की माफी से मुद्रास्फीति स्थायी रूप से 0.2 प्रतिशत बढ़ेगी। रिजर्व बैंक के एक दस्तावेज में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में 88,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी को लागू किया जाना है। इससे संभवतः स्थायी रूप से मुद्रास्फीति में 0.2 प्रतिशत का इजाफा होगा। देश में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा कृषि कर्ज को माफ करने की घोषणा की जाती है। इसका मकसद प्राकृतिक आपदा-फसल नुकसान से संकट झेल रहे किसानों को राहत प्रदान करना होता है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी 'मिंट स्ट्रीट मेमो' में कहा गया है कि ऋण माफी से मध्यम अवधि में राजकोषीय बोझ बढ़ेगा क्योंकि अनिवार्य रूप से यह करदाताओं से कर्ज लेने वालों की ओर स्थानांतरण होता है।

अब बैंकों में नहीं होगी धोखाधड़ी!

नई दिल्ली 12सितंबर(ए)। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता नियमावली (विजिलेंस मैनुअल 2017) जारी की है जिसमें धोखाधड़ी पर लगाम के लिए बैंकों को अपने कर्मचारियों के बारे में भी पूरी पड़ताल करने के लिए कहा है। साथ ही सी.वी.सी. ने बैंकों से अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) के साथ अपने कर्मचारी को जानिए (के.वाई.ई.) पर भी जोर देने को कहा है। इसमें कहा गया है कि कई तरह के धोखाधड़ी के मामलों में बैंक के अंदर के लोग शामिल रहते हैं या उन्हें अंदर के लोगों की मदद से अंजाम दिया जाता है। बैंकों को अपने कर्मचारियों की निगरानी के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। सी.वी.सी. ने कहा कि कर्मचारियों के पिछले जीवन के बारे में पता लगाना, निश्चित अवधि में उन्हें एक स्थान से दूसरी जगह भेजना, सतर्कता आकलन, ऑतरिक आडिट आदि के जरिये बैंक अपने कर्मचारियों के बारे में प्रभावी तरीके से जान सकते हैं। आयोग ने बैंकों को के.वाई.सी. के अलावा के.वाई.ई. और के.वाई.पी. 'अपने भागीदार के बारे में जानिए' पर भी विशेष ध्यान देने को कहा है। आयोग का कहना है कि आज के समय में बैंकिंग कामकाज में भागीदारों, एजेंट्स और वेंडर्स के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है। इसके अलावा बैंकिंग कामकाज की आउटसोर्सिंग भी होती है। कई ऐसी परिचालन गतिविधियां हैं जिनमें बाहरी एजेंसी के कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है और उनपर विश्वास करना पड़ता है। यदि बैंकों में धोखाधड़ी रोकनी है तो अपने भागीदारी की छानबीन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने विजिलेंस मैनुअल, 2017 यहां जारी किया।

बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान होने से दो सप्ताह में सब्जियों के दाम दोगुने

नई दिल्ली 12सितंबर(ए)। इस महीने के पहले 10 दिनों में सब्जियों के दाम करीब दोगुने हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि देश के प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में लगातार बारिश और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान होने के कारण सब्जियों की आपूर्ति कम हो रही है। सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि बैंगन के भाव में 81.8 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जिसका कारोबार आज मुंबई की थोक मंडियों में 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर हुआ। बंद गोभी 55.6 फीसदी महंगी हुई है।

मंडियों में आज इसका भाव 14 रुपये प्रति किलोग्राम बोला गया, जो इस महीने के प्रारंभ में 9 रुपये प्रति किलोग्राम था। भिंडी के दाम 26.5 फीसदी बढ़कर 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं, जो 1 सितंबर को 17 रुपये थे। कुछ को छोड़कर ज्यादातर सब्जियों के दाम चेन्नई में भी इसी दिशा में बढ़े हैं। वहां पिछले 11 दिनों में करेले की कीमतें 42 फीसदी बढ़कर 27 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। रोचक बात यह है कि दिल्ली की थोक मंडियों में सब्जियों के दाम अन्य महानगरों के मुताबिक घट-बढ़ रहे हैं। दिल्ली की थोक मंडियों में लगभग सभी सब्जियों की कीमतों में 73 फीसदी तक की गिरावट आई है।

अब विदेशी बेनामी सम्पत्तियों की बारी

मुम्बई12सितंबर(ए)। काले धन के खिलाफ मुहिम में मोदी सरकार के निशाने पर अब विदेशी बेनामी सम्पत्तियां हैं। आयकर विभाग इन विदेशी सम्पत्तियों पर वार करने की तैयारी में है। इस संबंध में विभाग ने अपनी 6 कंपनियों और सम्पत्तियों का खुलासा नहीं करने वाले 5 सर्राफा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है। बताया जा रहा है कि कर वंचना के लिए चर्चित ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में इन लोगों पर सम्पत्तियां और कंपनियां रखने का आरोप है। ये लोग सोने और हीरे के निर्यात कारोबार से जुड़े हैं तथा इनका भारत में अच्छा-खासा कारोबार है। इनकी कुल अघोषित विदेशी सम्पत्ति करीब 5000 करोड़ रुपए की बताई जाती है।

2013 में जारी सूची में थे 612 भारतीयों के नाम: इंटरनैशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वैस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आई.सी.आई.जे.) ने वर्ष 2013 में एक सूची जारी की थी जिसमें 612 भारतीयों के नाम थे। ये

पांचों कारोबारी इस सूची में शामिल हैं। इस संस्था ने विदेश में मौजूद हजारों गुप्त कंपनियों, ट्रस्टों और फंडों का खुलासा किया था। कर अधिकारियों के अनुसार इन मामलों में पक्के सबूत हैं। इन लोगों ने विदेशों में निवेश किया और गुप्त लेन-देन किया मगर अपने कर विवरण में इसे शामिल नहीं किया।

इन लोगों पर इस कैरेबियाई द्वीप की कंपनियों के शेयर और सम्पत्तियां रखने का आरोप है। ऐसा पहली बार है कि इस आइलैंड की सूची की जांच में आयकर विभाग को भारी मात्रा में कर चोरी का पता चला है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग को विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है जिनका इन लोगों के प्रोफाइल और देश-विदेश में घोषित उनकी सम्पत्तियों से मिलान किया गया है। विभाग के पास मौजूद दस्तावेजों से भारी मात्रा में बेनामी विदेशी धन का खुलासा हुआ है।

292 लोगों और फर्मों की प्रारंभिक जांच: अभी तक विभाग ने 292 लोगों और फर्मों की प्रारंभिक जांच की है। ये सभी मुम्बई के हैं। इनमें से 151 मामले कार्रवाई के लायक हैं और जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार 15 मामलों में अभियोजन शुरू हो गया है जिनमें से 5 की मुम्बई में विशेष अदालत में सुनवाई होगी। इसके अलावा विभाग की जांच शाखा ने आकलन शाखा को 19 मामले भेजे हैं। इनमें 3117 करोड़ रुपए का अघोषित विदेशी धन शामिल है। मुम्बई के कम से कम 7 नामी लोगों के यहां तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान कई विदेशी बैंक खातों का पता चला है जिनका जाहिर तौर पर खुलासा नहीं किया गया था। डायमंड ज्वैलरी के एक निर्यातक के यहां 2150 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा लेन-देन की बात सामने आई है। एक अन्य मामले में कंरदाता का लाभार्थी के रूप में पता चला। उसका सिंगापुर के यू.बी.एस. ए.जी. में खाता है। अधिकारी ने बताया कि इस खाते से उस शख्स की भारत में मौजूद कंपनियों के खातों में भुगतान किया गया। इस बीच आयकर अधिकारी पनामा खुलासे की जांच में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह पनामा के अधिकारियों द्वारा सूचना न दिया जाना है। शुक्रवार को सी.बी.डी.टी. के अधिकारियों की बैठक में भी यह मामला उठा।

अप्रैल-अगस्त में 17.5 प्रतिशत बढ़ा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

नई दिल्ली 12सितंबर(ए)। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 5 महीनों के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17.5 फीसदी बढ़कर 2.24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसकी मुख्य वजह इंडिविजुअल्स द्वारा जमा किया गया इनकम टैक्स रहा। यह बजट में वित्त वर्ष के लिए डायरेक्ट टैक्सेस के कुल इस्टीमेट का 22.9 फीसदी है, जिसमें पर्सनल इनकम और कॉरपोरेट टैक्स शामिल हैं। सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स से 9.80 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अगस्त 2017 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, नेट रिफंड्स 2.24 लाख करोड़ रुपए रहा, जो बीते साल की समान अवधि की तुलना में 17.5 फीसदी ज्यादा है। ग्रास रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन (सिक्युरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) 16 फीसदी बढ़ी है, वहीं कॉरपोरेट टैक्स 5 फीसदी बढ़ा है।

18 फीसदी बढ़ा कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन : अप्रैल-अगस्त 2017 के दौरान 74,089 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए, जो बीते साल की समान अवधि की तुलना में 7.2 फीसदी कम है। रिफंड्स एडजस्ट करने के बाद कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में कुल 18.1 फीसदी की ग्रोथ रही, जबकि इनकम टैक्स कलेक्शन में 16.5 फीसदी की ग्रोथ रही। वहीं 2016-17 में अप्रैल-अगस्त के दौरान डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.03 फीसदी बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए रहा था।

केवायसी ही नहीं 'अपने इम्प्लॉई को भी जानें' बैंक, तभी रुकेंगे फ्रॉड: सीवीसी

नई दिल्ली 12सितंबर(ए)। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (सीवीसी) ने बैंकों से कहा है कि उन्हें फाड रोकने के लिए केवल नो योर कस्टमर (केवाईसी) पर ही फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि 'नो यो इम्प्लॉई' भी चेक करना चाहिए। सीवीसी ने हाल ही में जारी विजिलेंस मैनुअल में यह बात कही है। सीवीसी का कहना है कि फाड के कई मामले में बैंकों के भीतर के इम्प्लॉई या इनसे जुड़े लोगों के जरिए ही हुए हैं। बैंकों को अपने स्टाफ के मामले में लगातार सतर्क रहने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

नो योर इम्प्लाई नॉर्म्स प्रभावी तरीके से हो लागू

सीवीसी ने नो योर इम्प्लॉई (केवाईई) और नो योर पार्टनर (केवाईपी) नॉर्म्स की आवश्यकता जताई। कमीशन ने कहा कि नो योर इम्प्लाई नॉर्म्स को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इम्प्लॉई के बैकग्राउंड की जांच-पड़ताल की तकनीक, इंटरनल ऑडिट, विजिलेंस असिसमेंट जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पार्टनर्स की जांच का प्रभावी मैकेनिज्म जरूरी

सीवीसी मैनुअल में कहा है कि आज की बैंकिंग जरूरत के तहत पार्टनर्स, एजेंट्स और वेंडर्स के साथ काम करना होता है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग और कई ऑपरेशनल एक्टिविटी भी बैंकिंग कामकाज में शामिल होती है, जिसमें बाहरी एजेंसी के इम्प्लॉई पर भरोसा करना होता है। कई तरह की एक्टिविटी जैसेकि कैश लॉजिस्टिक का आईटी और डाटा मैनेजमेंट थर्ड पार्टी के भरोसा किया जा जाता है। बैंकिंग करस्पॉडेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स भी अब बैंकों से सीधे तौर पर जुड़े हैं। ऐसे में यदि फ्राड को रोकना है तो बैंकों के पास अपने पार्टनर्स की निगरानी और जांच का प्रभावी मैकेनिज्म होना चाहिए।

लोन प्रोसेस से जुड़े होते हैं सीए और वैल्यूअर्स

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी विजिलेंस मैनुअल, 2017 में कहा गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैल्यूअर्स और एडवोकेट्स जैसे अन्य प्रोफेशनल्स भी लोन असेसमेंट और मंजूरी जैसे कामों से जुड़े होते हैं, इसलिए सेफगार्ड लेना काफी जरूरी है। मैनुअल में कहा गया कि केवाईसी नियमों का पालन करने के लिए सुझाए गए डॉक्यूमेंट्स अकाउंट होल्डर से ही लिए जाने चाहिए।

एचडीएफसी बैंक बनी देश की दूसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी

नई दिल्ली12सितंबर(ए)। एचडीएफसी बैंक मंगलवार को टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए देश की दूसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी बन गई। अच्छे तिमाही नतीजे से स्टॉक में आई तेजी से एचडीएफसी बैंक ने मार्केट कैप के मामले टीसीएस को पीछे छोड़ दिया। आज के कारोबार में एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 0.93 फीसदी बढ़कर 1840 के स्तर पर खुला। इसी के साथ स्टॉक ने 52 हफ्ते की नई ऊंचाई बनाया। स्टॉक के 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचने से एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 473,944 करोड़ रुपए हो गया। वहीं टीसीएस का मार्केट कैप 470,934 करोड़ रुपए था। टीसीएस से मार्केट कैप ज्यादा होने की वजह से एचडीएफसी बैंक टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले नंबर पर कायम है।

एटीएम कार्ड का नंबर पूछकर निकाली राशि, बैंक को लगाया जुर्माना

मंदसौर 12सितंबर(ए)। जिला उपभोक्ता निपटारा फोरम ने फोन पर ए.टी.एम. कार्ड का नंबर पूछ कर की जा रही धोखाधड़ी को भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) प्रबंधन की बैंक खातों में सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही माना है। फोरम ने बैंक को एक उपभोक्ता के खाते में से निकाली गई राशि फिर से जमा करवाने का आदेश दिया है।

शिकायतकर्त्ता प्रभु लाल हिन्दल का भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की टीलाखेड़ा पिपलिया मंडी ब्रांच में बचत खाता है। 27 मई, 2016 को हिन्दल को फोन कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपने-आपको भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच से बताकर ए.टी.एम. कार्ड बंद होने और आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने की बात कही।

उसने उपभोक्ता से ए.टी.एम. पर लिखा 19 अंकों का नंबर

पूछा। प्रभु लाल ने ए.टी.एम. का नंबर उसे बता दिया। उसके बाद 8 बार हुई ऑनलाइन खरीदारी में खाते में से 42,760 रुपए की राशि निकाल ली गई जिसकी शिकायत प्रभु लाल ने 28 मई, 2016 को बैंक, एस.पी. और स्थानीय थाने को दी। इसके साथ ही उपभोक्ता फोरम में भी परिवाद पेश कर दिया। इस दौरान निकाली गई राशि में से 4000 रुपए वापस खाते में जमा हो गए परंतु बाकी राशि नहीं आई।

उपभोक्ता फोरम ने मुकदमे पर सुनवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ किए जा रहे ट्रांजैक्शन की सुरक्षा में कहीं न कहीं लापरवाही मानते हुए पीड़ित के खाते में बाकी रहती 38,760 रुपए की राशि जमा करवाने और अदालती खर्च के तौर पर 2000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जेब्रोनिक्स ने अपने नये 'फुल मून' टॉवर स्पीकर्स लॉन्च किये

मुम्बई 12 सितंबर(ए)। जैब्रोनिक्स ने अपने नये 'फुल मून' टॉवर स्पीकर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये संगीत सुनने के लिए पूर्ण रूप से विकसित स्टीरियो साउंड को पेशकश करेंगे।

शानदार इंजीनियरिंग एवं आधुनिक डिजाइन वाले ये स्पीकर वुडेन एनक्लोजर से सुसज्जित हैं। हाई पावर डिजिट एम्प्लीफायर टेक्नोलॉजी के साथ, 10.16cms(4)x 4 मिडरेंज, 3.81cms(1.5)X2 ट्वीटर और 20.32cms(8)x2 सबवूफर ड्राइवर के साथ आप हर बीट को एकदम साफ सुन सकते हैं।200वाट्स आरएमएस और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित स्पीकर को पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जा सकता है डुयुअल माइक्रोफोन जैक्स, दो वायरलेस माइक्रोफोन से युक्त ये स्पीकर आरजीबी लाइट्स के साथ आते हैं। फुल मून टॉवर स्पीकर्स को आपके पीसी, टीवी, एमपी3 प्लेयर या डीवीडी प्लेयर से आसानी से जोड़ा जा सकता है। मोबाइल फोन को भी 3.0 ईडीआर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिये स्पीकर्स से भी कनेक्ट कर सकते

चीन में बंद होंगी ईंधन से चलने वाली कारें, इलैक्ट्रिक कारों का बढ़ेगा चलन

पेइचिंग12सितंबर(ए)। चीन में बढ़ रहे प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए ईंधन से चलने वाली कारों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें बंद करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। चीन को दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ऐसे में इस देश में इलैक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने से पूरी दुनिया में इलैक्ट्रिक कारों के चलन में तेजी आने की सम्भावना है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन में पैट्रोल-डीजल वाहनों पर बैन की तैयारी शुरू हो गई है।देश में वाहन निर्माता कंपनियों को डैडलाइन दे दी गई है कि वे अब पैट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की बिक्री बंद करें ताकि इलैक्ट्रिक व्हीकल विकसित करने में तेजी लाई जा सके। इंडस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के वाइस मिनिस्टर शिन गुओबिन ने बताया है कि सरकार एक टाइमटेबल पर काम कर रही है ताकि ईंधन से चलने वाले वाहनों की प्रोडक्शन को शुरू किया जा सके। इलैक्ट्रिक कारों के आने से चीन के ऑटो उद्योग में वृद्धि तो होगी ही साथ ही इसका वातावरण पर भी काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

चीन में इलैक्ट्रिक कारों की बिक्री में हुई बढ़ौतरी: चीन की पैसेंजर कार एसोसिएशन के मुताबिक वाहन निर्माता कम्पनी बी.वाई.डी. ने इस साल के पहले 7 महीनों में 46,885 इलैक्ट्रिक व हाईब्रिड व्हीकल्स बेचे हैं। इसके अलावा बी.ए.आई.सी. मोटर की इलैक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन ने 7 महीनों में ही 36,084 यूनिट्स बेचकर एक नई उपलब्धि को हासिल किया है। अब तक चीन

में इलैक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कम्पनी बी.वाई.डी. ने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि की है।

टैस्ला चीन में बनाएगी सस्ती इलैक्ट्रिक कारें: अमरीकी कार निर्माता कम्पनी टैस्ला ने जून में जानकारी दी थी कि कम्पनी शंघाई सरकार के साथ काम कर रही है ताकि चीन में बेहतर इलैक्ट्रिक कारों को बनाया जाए ताकि कम कीमत में ये कारें बिक्री के लिए उपलब्ध की जा सकें। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया इलैक्ट्रिक कारों से मिलने वाले पर्यावरण के फायदों को समझते हुए इन्हें अपनाने पर जोर देगी।

फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे और जर्मनी में भी बैन की तैयारी: पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और पैरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस साल 2040 तक देश में पैट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने जा रहा है। फ्रांस के पर्यावरण मंत्री निकोलस उलो ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध की घोषणा को पैरिस पर्यावरण समझौते के प्रति फ्रांस की नई प्रतिबद्धता बताया है। उलो ने कहा कि फ्रांस ने 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की योजना बनाई है।